www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 अंक – 306 जौनपुर शनिवार, 27 जून 2026 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वेनेजुएला में भूकंप का कहर, 235 लोगों की गई जान

काराकास, (एजेंसी)। वेनेजुएला में बुधवार शाम आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मृतकों की संख्या पहले बताए गए 32 से बढ़कर 235 हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश के उत्तरी इलाकों में आए दो भीषण भूकंपों के बाद बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए तीन प्रमुख कदमों की घोषणा की है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए निजी कंपनियों को मलबा हटाने वाले भारी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विशेष राहत कोष बनाने और प्रभावित कारोबारियों के लिए विशेष ऋण सुविधा शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देश में कई दशकों बाद आए सबसे भीषण भूकंपों से निपटने के लिए उठाए गए हैं। विदेश मंत्री इवान गिल ने गुरुवार को कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय सहायता के समन्वय के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय देशों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कम से कम एक दर्जन देशों ने वेनेजुएला को हरसंभव सहायता देने की पेशकश की है। वेनेजुएला में बुधवार को लगातार दो भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 7.2 और 7.5 थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 26 जून (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी क्रियान्वयन में उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक्स पर अपने संदेश में कहा कि केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास देश की भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने और भारत को ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, कौशल विकास, मातृभाषा में शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा तथा विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने पर विशेष बल दिया जाता रहा है। साथ ही केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

इमाम हुसैन की कुर्बानी देती है साहस का संदेश : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उन्हें सत्य, न्याय, साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी आज भी करोड़ों लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी अनगिनत लोगों को सत्य और न्याय की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की अमर शक्ति की भी याद दिलाती है। हजरत इमाम हुसैन, पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के नवासे (दोहिते), हजरत अली और हजरत फातिमा के छोटे पुत्र थे। इस्लाम के इतिहास में उनका स्थान बेहद सम्मानित और महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी में कर्बला के मैदान में सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इतिहास के अनुसार, इमाम हुसैन ने अत्याचारी शासक यजीद के सामने झुकने और उसकी सत्ता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद कर्बला के युद्ध में उन्होंने अपने परिवार और 72 वफादार साथियों के साथ तीन दिन तक भूखे–प्यासे रहकर संघर्ष किया और शहादत स्वीकार कर ली, लेकिन अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। यह शहादत आज भी इस्लाम में अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है।

राममंदिर चढ़ावा विवाद पर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा, कहा– आस्था से खिलवाड़ न करें

देवरिया, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शुक्रवार को तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि मामले में ष्दूध का दूध और पानी का पानीष किया जाएगा। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि रामभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ न करें और यदि किसी के पास कोई प्रमाण है तो उसे एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत करे। देवरिया में 456 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान भी स्पष्ट किया था कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है और

कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस पवित्र नगरी पर बेबुनियाद आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। भगवान श्रीराम की मर्यादा का पालन करना सीखिए। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है, लेकिन बिना तथ्यों के आरोप लगाकर जनभावनाओं को आहत करना भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े ठोस तथ्य या साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय एसआईटी को उपलब्ध कराना चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड प्रवास पर, किसानों के बीच जाएंगे केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। उनके दौरे में किसान, कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा। अपने इस दौरे में वे एक ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेंगे, वहीं दूसरी ओर खेत–खलिहान तक पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे तथा पूर्व छात्रों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। खेती, किसान और गांव की बेहतरी के उद्देश्य

से शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड प्रवास के दौरान विभिन्न बैठकों, विभागीय समीक्षा कार्यक्रम और फील्ड विजिट में शामिल होंगे। सुबह केंद्रीय मंत्री चौहान गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में पूर्व विद्यार्थियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं रुद्रपुर में "खेत बचाओ अभियान" के अंतर्गत केंद्रीय चौहान किसान संवाद, खेतों का भ्रमण, फसल का जायजा और कृषि विषयों पर प्रत्यक्ष चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा किसानों की सहभागिता रहेगी। इसके बाद पंत नगर में आयोजित मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी बैठक में राज्य में कृषि के समग्र विकास, किसान हितों, ग्रामीण विकास योजनाओं, केंद्र और राज्य की समन्वित कार्यप्रणाली तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस दौरान यह भी समीक्षा होगी कि योजनाओं का लाभ किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है और आगे किन क्षेत्रों में गति बढ़ाने की जरूरत है।

ड्रग्स तस्करों पर सख्ती, नशे के शिकार लोगों के लिए सहानुभूति – अमित शाह

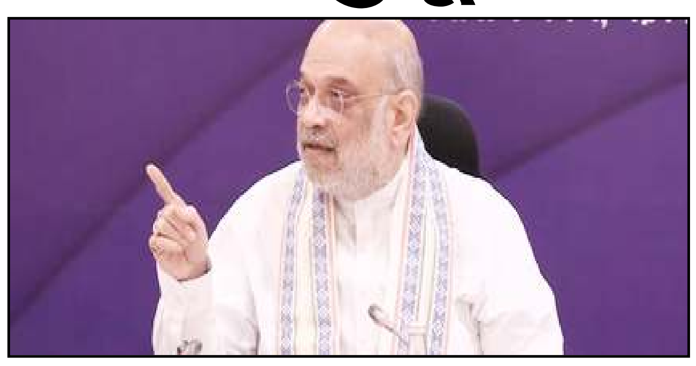

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश आज नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और आने वाले तीन साल बेहद अहम होंगे। अमित शाह ने कहा कि 26 जून भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। एक ओर देश नशे के खिलाफ प्रभावी रोडमैप तैयार कर रहा है, वहीं आज महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती भी है। बंकिम बाबू ने गुलामी के दौर में देश के आत्मविश्वास को जगाने का काम किया और वंदे मातरम जैसी अमर रचना दी। उन्होंने कहा, वंदे मातरम केवल एक नारा या गीत नहीं है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और देश के पुनर्निर्माण का मंत्र है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का सबसे बड़ा उद्घोष भी वंदे मातरम ही था। इतिहास गवाह है कि देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी अपने अंतिम शब्द के रूप में वंदे मातरम का ही उच्चारण करते थे। गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून–व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देश के अगले 100 वर्षों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सभी सरकारों, विभागों, संतों, युवाओं और मातृशक्ति को एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से काम करना होगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बहुत करीब, लेकिन टैरिफ में बढ़त मिले बिना इस पर साइन नहीं करेगा भारत - गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लंदन में में कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील तब तक लागू नहीं होगी, जब तक भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ लाभ नहीं मिलता। हालांकि, गाोयल ने यह कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील श्बहुत करीबश है, लेकिन भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले टैरिफ में बढ़त मिले बिना इस पर साइन नहीं करेगा। गोयल ने लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम (आईजीएफ) यूके–इंडिया वीक को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर आगे बढ़ने से पहले भारत इस पर स्पष्टता चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वह प्रतिस्पर्धा करने वाली दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अपनी बढ़त को कैसे बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, हमें यह पक्का करना है कि हमें उन देशों के मुकाबले

कॉम्पिटिटिव फायदा मिले जो विकास के उसी चरण में हैं या जिनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भारत जैसी ही है। चाहे वह वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन हो, या बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारे सभी पड़ोसी देश हों। इस बीच भारत–अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर यूएस–इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ मुकेश आघी कहते हैं, ष्ये मामला तकनीकी नहीं है। मुझे लगता है कि भारत का रुख यह रहा है कि श्हमें प्रेफरेंशियल टैरिफ (वरीयता वाला टैरिफ) चाहिए', यानी हमें अपने पड़ोसियों के मुकाबले कम टैरिफ दिया जाए क्योंकि इससे हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव (प्रतिस्पर्धी) बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि बात 10 फीसदी या 20 फीसदी की नहीं है, बल्कि असल बात पड़ोसियों से कम टैरिफ पाने की भी है। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि अभी भारत पर टैरिफ 12.5 फीसदी है और पाकिस्तान पर 10 फीसदी। भारत का कोई भी राजनीतिक दल या नेता इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इससे मूल रूप से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। यूएस–इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ मुकेश आघी ने आगे कहा कि इसलिए, इस मसले को सुलझाना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है।

असम सरकार ने उच्च शिक्षा योजनाओं के तहत 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया – सरमा

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य बड़े कदम उठाए हैं। इस क्रम में दो प्रमुख सहायता योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को समर्थन देने के लिए 2025–26 के दौरान 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी और मुख्यमंत्री निजुत बाबू सोनी योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त निवेश किया गया है ताकि वित्तीय बाधाएं योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने से न रोकें। सरमा ने कहा कि पिछले वर्ष, हमने असम की सबसे बड़ी ताकत, हमारे युवाओं में 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। निजुत मोइना और बाबू असोनी योजनाओं के माध्यम से, हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे असम में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन

सकें। मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी योजना से 2025–26 के दौरान 2,00,727 छात्रों को लाभ हुआ, जिसमें कुल 167.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई। मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना के तहत, इसी अवधि में 49,438 लाभार्थियों को 9.78 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। दोनों योजनाओं को मिलाकर, 2.5 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ, जिसमें कुल वित्तीय सहायता 176 करोड़ रुपए से अधिक हो गई।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईरान के तेल मंत्री से की तेहरान और नई दिल्ली के बीच ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान गुरुवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, गुरुग्राम (हरियाणा) में गुरुवार को आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान पाकनेजाद ने अपने भारतीय समकक्ष से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों नेताओं ने तेल और ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने, उसे मजबूत करने और नए अवसर तलाशने के महत्व पर जोर दिया। भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में बताया, "ईरान इस्लामी गणराज्य के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने गुरुवार को भारत के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के मौके पर भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने तेल, गैस और ऊर्जा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही, तेहरान और नई दिल्ली के बीच ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।" आईआरएनए की रिपोर्ट के अनुसार, भारत पहले ईरानी कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन 2019 में अमेरिका की ओर से ईरान के तेल निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात रोक दिया था। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 25–26 जून तक आयोजित की जा रही है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश शामिल हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में कहा, "ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसेन पाकनेजाद से मुलाकात हुई।

मनीष श्रीवास्तव को राज्यमंत्री का जनसम्पर्क अधिकारी बनाये जाने पर हुआ भव्य स्वागत

देश की उपासना
संवाददाता प्रवीण अस्थाना

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री गिरीश चन्द्र यादव जी के जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त होने पर श्री मनीष श्रीवास्तव जी का आज भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 के महासचिव एवं सहकार भारती के जिला मंत्री श्री नवनीत श्रीवास्तव जी के जहाँगीराबाद स्थित आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में मौज मस्ती ग्रुप के सदस्यों ने श्री मनीष श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ एवं बुके देकर सम्मानित किया। स्वागत करने वालों में श्री प्रमोद श्रीवास्तव, श्री धीरज श्रीवास्तव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री सुप्रतीक गुप्ता, श्री गौरव श्रीवास्तव,

श्री संजीव केसरवानी, श्री शशि श्रीवास्तव 'गुड्डू', एडवोकेट श्री शिव गोविन्द लाल श्रीवास्तव, श्री प्रवीण श्रीवास्तव, श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री शिवम श्रीवास्तव, श्री सत्यम श्रीवास्तव, श्री किशलय श्रीवास्तव एवं श्री प्रखर श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री मनीष श्रीवास्तव ने कहा, मुझे मिली यह नई जिम्मेदारी जनसेवा का अवसर है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव से करूंगा। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभारी हूँ। कार्यक्रम के अंत में एडवोकेट श्री शिव गोविन्द लाल श्रीवास्तव, श्री शशि श्रीवास्तव 'गुड्डू' एवं कार्यक्रम के आयोजक श्री नवनीत श्रीवास्तव ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मनीष श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं और पूर्व में नगर पालिका परिषद जौनपुर के नामित सभासद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

संपादकीय

गहरी यांत्रणा से गुजरना

न्याय होने से पहले न्यूजक्लिक से जुड़े लोगों को गहरी यांत्रणा से गुजरना पड़ा। एक चलती हुई वेबसाइट मृतप्राय हो गई, दर्जनों कर्मचारियों की नौकरी गई, उनमें से बहुतों के यहां छापे पड़े। इनकी भरपाई कैसे होगी? छह साल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की यांत्रणा झेलने के बाद आखिरकार वेबसाइट न्यूजक्लिक को इंसाफ मिला। मुकदमा खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कहा कि न्यूजक्लिक के खिलाफ ना सिर्फ जारी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता पर मनमाना हमला तथा शक्ति के दुरुपयोग का मामला भी है। ईडी के आरोपों को श्पूर्णतरू गढ़ा हुआ और निराधारश्र ठहराते हुए न्यायालय ने कहा कि वेबसाइट के खिलाफ दूर से संकेत देने लायक भी कोई सबूत नहीं पेश नहीं किया गया। जबकि आरोप मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत लगाया गया था। बुधवार को ही हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने जम्मू–कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज पर यूएपीए के तहत जारी मुकदमे में जमानत दे दी। यह मामला पांच साल पुराना हो चुका है, मगर हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभी इसमें मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने की दूर–दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय ने श्जेल अपवाद और बेल नियमश्र का सिद्धांत लागू किया। ये दोनों मामले देश में कानून के राज और न्याय की भावना के रोजमर्रा के स्तर पर जारी उल्लंघन की मिसालें हैं। मुद्दा सिर्फ परवेज या उन जैसे लोगों को सताने का नहीं है। सवाल है कि उनके खिलाफ अभियोग पक्ष के पास अकाट्य साक्ष्य हैं, तो न्यायिक कार्यवाही में उन्हें सिद्ध कर कानून सजा दिलाने की तत्परता वह क्यों नहीं दिखाता? ऐसा नजरिया क्यों अपनाया गया है, जिससे प्रक्रिया को ही दंड बना देने का अस्वीकार्य चलन अस्तित्व में आया है? यह न्यूजक्लिक की खुशकिस्मती है कि उस पर मुकदमा चला। बहरहाल, न्याय होने से पहले उसके संपादक एवं अन्य पदाधिकारियों को महीनों जेल में गुजारने पड़े, एक चलती हुई वेबसाइट मृतप्राय हो गई, दर्जनों कर्मचारियों की नौकरी गई, उनमें से बहुतों के घर पर छापे पड़े जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंची। आखिर इन सबकी भरपाई कैसे होगी? अतरू क्या अब वक्त नहीं आ गया है, जब निराधार आरोप गढ़ने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए? साथ ही जिनकी जिंदगी अस्थिर और परेशान होती है, उन्हें उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए?

जल शक्ति विकसित भारत की यात्रा को दे रही है गति

सी. आर. पाटिल

क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम है? या फिर स्वच्छ भारत मिशन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता अभियान है, जिसने लोगों की सोच और व्यवहार में अभूतपूर्व बदलाव लाया है? और क्या आपको पता है कि नमामि गंगे आज दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी नदी पुनर्जीवन योजनाओं में शामिल है? ये सभी पहल केवल सरकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि इस बात का उदाहरण हैं कि 145 करोड़ आबादी वाला भारत किस तरह पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब इतिहासकार भारत की विकास यात्रा को देखेंगे, तो संभव है कि वे पिछले 12 वर्षों को वह दौर बताएं, जब श्जलश देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। मानव सम्मान, आर्थिक विकास, जनस्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संरक्षण पर पानी जितना प्रभाव डालता है, उतना शायद ही कोई दूसरा क्षेत्र डालता हो। लेकिन कई दशकों तक भारत में जल संबंधी समस्याओं का समाधान अलग–अलग और बिखरे हुए तरीकों से किया जाता रहा। पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत, गंभीर और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। पिछले 12 वर्षों में जल क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर निवेश और काम हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस बदलाव की अहमियत केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। आज पानी को पूरे देश की साझा प्राथमिकता माना जा रहा है, जिसमें सभी विभाग, राज्य, समुदाय और आने वाली पीढ़ियाँ भागीदार हैं। पहले जल क्षेत्र को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल क्षेत्र की योजना, प्रबंधन और सेवाओं से जुड़ी वर्षों पुरानी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई। इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है। जब यह मिशन शुरू हुआ था, तब केवल लगभग 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों, यानी करीब 17 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही नल से जल की सुविधा थी। आज 15.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों, यानी 81 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुँच चुका है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराना है। लाखों परिवारों, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए यह केवल पानी की सुविधा नहीं है, बल्कि उनके जीवन में आया एक बड़ा बदलाव है। अध्ययनों के अनुसार, पहले भारत की ग्रामीण महिलाओं को हर साल पानी लाने में अरबों घंटे खर्च करने पड़ते थे। अब घर–घर नल से पानी पहुंचने के कारण हर दिन 5.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति–घंटों की बचत हो रही है। जो समय पहले पानी लाने में लगता था, अब उसका उपयोग पढ़ाई, रोजगार, बच्चों की देखभाल और आय बढ़ाने वाले कामों में हो रहा है। साथ ही, सुरक्षित पेयजल मिलने से पानी से फैलने वाली बीमारियाँ कम हुई हैं, जिससे लोगों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटा है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ने भी देश में बड़ा बदलाव लाया है। इस अभियान ने दिखाया कि लोगों की सोच में बदलाव, जनभागीदारी और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति मिलकर बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की वजह से 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच दस्त से होने वाली 3 लाख से अधिक मौतों को रोका जा सका। घर–घर शौचालय बनने से करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को सम्मान, निजता और सुरक्षा मिली। इस तरह स्वच्छता केवल एक सुविधा नहीं रही, बल्कि जनस्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान का एक बड़ा जनआंदोलन बन गई। गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के बाद अब देश स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक एवं टिकाऊ प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के क्षेत्र में भी दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक चलाया है। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत से ष्जल संचय जन भागीदारीष अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 31 मई 2026 तक देशभर में 1.55 करोड़ से अधिक वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। यह अभियान दिखाता है कि जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी और सामूहिक प्रयास कितने प्रभावी हो सकते हैं। इन प्रयासों का सकारात्मक असर अब भूजल की स्थिति में भी दिखाई देने लगा है। हाल के आकलनों के अनुसार, देश के कई हिस्सों में भूजल का स्तर बेहतर हुआ है और जिन क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा था, उनकी संख्या में भी कमी आई है।

बड़ा मिशन लेकर सेशेल्स जा रहे हैं मोदी, हिंद महासागर में भारत का मास्टरस्ट्रोक देखेगी दुनिया

नीरज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 से 29 जून तक होने वाली सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक सक्रियता और वैश्विक भूमिका को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी की भागीदारी यह संकेत देती है कि भारत अब हिंद महासागर में अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा, विकास और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि सेशेल्स 115 द्वीपों वाला छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मोजाम्बिक चौनल के निकट उन समुद्री मार्गों पर स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी कारण अमेरिका, चीन और यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में भारत का सेशेल्स के साथ संबंधा मजबूत करना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भारत द्वारा सेशेल्स तटरक्षक बल को एक तीव्र गश्ती पोत सौंपना है। इससे पहले भारत दो डोर्नियर विमान, कई गश्ती नौकाएं तथा तटीय निगरानी राडार प्रणाली भी सेशेल्स को प्रदान कर चुका है। भारतीय रक्षा कर्मियों की तैनाती और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी है। समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सेशेल्स भारत पर भरोसा करता है। यही कारण है कि यह यात्रा हिंद महासागर में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत की महासागर दृष्टि के अंतर्गत सेशेल्स को विशेष स्थान प्राप्त है। भारत अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की भूमिका निभा रहा है। सेशेल्स का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बनने का संकेत भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस समूह में भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका पहले से शामिल हैं। यदि सेशेल्स भी पूर्ण सदस्य बनता है, तो हिंद महासागर में भारत के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और मजबूत होगी। हम आपको बता दें कि मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा सहयोग के साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन, समुद्री निगरानी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। फरवरी 2026 में भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें ऋण सहायता और अनुदान दोनों शामिल हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सौर ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। यह दर्शाता है कि भारत केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विकास साझेदारी के माध्यम से भी अपने मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक संबंधा बना रहा है। हम आपको बता दें कि भारत और सेशेल्स के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरे हैं। वर्ष 1770 में भारतीयों का पहला समूह वहां पहुंचा था। आज लगभग 15 हजार भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं। गुजराती और तमिल समुदाय व्यापार, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद दोनों देशों के सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगा। यह यात्रा वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार किया है। चीन की समुद्री परियोजनाएं, बंदरगाह निवेश और सामरिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में सेशेल्स जैसे देशों के साथ भारत का गहरा सहयोग यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिंद महासागर में भारत अपनी पारंपरिक भूमिका को और सशक्त बना रहा है। भारत की नीति अब केवल "पड़ोसी प्रथम" तक सीमित

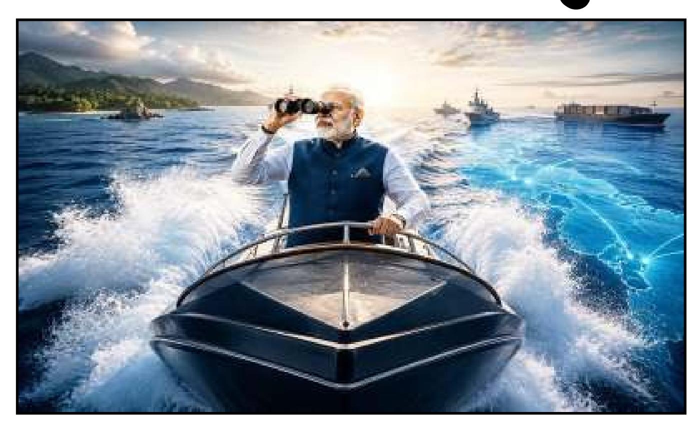

नहीं रही, बल्कि वह "ग्लोबल साउथ" के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरना चाहता है। सेशेल्स यात्रा इसी व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। यह दोनों देशों के राजनीतिक विश्वास और घनिष्ठता का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और रक्षा दल की भागीदारी भी यह दिखाती है कि दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, समुद्री सुरक्षा नीति और वैश्विक प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेत है। यह यात्रा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के केंद्र में स्थापित करने के साथ–साथ चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच संतुलन बनाने में भी सहायक होगी। विकास सहायता, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और समुद्री साझेदारी के माध्यम से भारत यह संदेश दे रहा है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और साझा समृद्धि का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है।

घरेलू मोर्चे पर झटके खा रहे राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़े असर के राजनीतिक व कूटनीतिक मायने

कमलेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (क्वदंसक ज्तनउच) को हाल के दिनों में घरेलू मोर्चे पर दो बड़े झटके लगे हैं, जिनका असर उनकी राजनीतिक ताकत, चुनावी रणनीति और राष्ट्रपति पद की सीमाओं पर पड़ सकता है। लिहाजा विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी इन घटनाओं का असर लाजिमी है। पहले हम बात करते हैं, उन दो बड़े झटके का–जहां पहला झटकारू मतदान संबंधी आदेश पर अदालत की रोक का है, वहीं दूसरा झटका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बढ़ता न्यायिक अंकुश है। उल्लेखनीय है कि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनावी नियम तय करना राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यों और कांग्रेस का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की कई नीतियांकृजैसे व्यापक टैरिफ, दूसरी प्रशासनिक एजेंसियों पर नियंत्रण और कुछ आव्रजन कदम अदालतों में चुनौती का सामना कर रही हैं। गौरतलब है कि इसी वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उनके व्यापक टैरिफ अधिकारों को खारिज करते हुए कहा कि कराधान और शुल्क निर्धारण का मूल अधिकार कांग्रेस के पास है। इसे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे पर बड़ा आघात माना गया। यह स्थिति दुनिया के अघोषित थानेदार के लिए उचित नहीं है। इसके निम्नलिखित राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। पहला, मजबूत राष्ट्रपति की छवि को चुनौतीरू ट्रंप ने स्वयं को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया है जो तेजी से निर्णय लेकर व्यवस्था बदल सकते हैं। अदालतों द्वारा बार–बार हस्तक्षेप होने से उनके समर्थकों के बीच यह धारणा बन सकती है कि संस्थागत ढांचा उनकी नीतियों को रोक रहा है। दूसरा, रिपब्लिकन आधार का और ध्रुवीकरणरू ट्रंप इन फैसलों को न्यायिक सक्रियता या डीप स्टेट की बाधा बताकर अपने समर्थकों को और अधिक संगठित करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे रिपब्लिकन मतदाता आधार में लामबंदी बढ़ सकती है। तीसरा, डेमोक्रेटिक पार्टी को राजनीतिक अवसररू डेमोक्रेट्स इन घटनाओं को संवैधानिक संस्थाओं की जीत और सत्ता के केंद्रीकरण पर अंकुश के रूप में पेश कर रहे हैं। इससे वे 2026 के मध्यावधि चुनावों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं। चौथा, कांग्रेस बनाम राष्ट्रपति की बहस तेजरू टैरिफ और चुनावी नियमों पर आए फैसलों ने यह संदेश दिया है कि अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं हैं। इससे कार्यपालिका और कांग्रेस के बीच अधिकारों की खींचतान और बढ़ सकती है। पांचवां, 2026 मध्यावधि चुनावों पर प्रभाव यदि ट्रंप अपनी प्रमुख नीतियों को लागू कराने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बताएगा। वहीं ट्रंप समर्थक इसे ष्व्यवस्था बनाम जनता की लड़ाई के रूप में प्रचारित कर सकते हैं। इसलिए ये झटके राजनीतिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ट्रंप के लिए सहानुभूति भी पैदा कर सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये दोहरे झटके केवल कानूनी पराजय नहीं हैं। इनके केंद्र में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन है। आने वाले महीनों में यह संघर्ष अमेरिकी राजनीति का प्रमुख विषय बन सकता है और 2026 के मध्यावधि चुनावों की दिशा भी प्रभावित कर सकता है। खास बात तो यह कि घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की शक्तियों को मिले इन झटकों का प्रभाव केवल अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति और कूटनीति पर भी दूरगामी असर डाल सकता है। पहला, अमेरिकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्नरू जब किसी राष्ट्रपति की प्रमुख नीतियां अदालतों या संस्थागत बाधाओं से रुकती हैं, तो सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी दोनों देशों के मन में यह सवाल उठता है कि अमेरिका की घोषित नीतियां कितनी स्थायी हैं। इससे अमेरिकी वादों और समझौतों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। दूसरा, ष्टैरिफ कूटनीतिष की धार कमजोररू ट्रंप ने व्यापार शुल्क (टैरिफ) को विदेश नीति के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके व्यापक टैरिफ अधिकारों को सीमित किए जाने से चीन, यूरोपीय संघ, भारत, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर दबाव बनाने की उनकी क्षमता कम हुई है। तीसरा, चीन को रणनीतिक अवसररू यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक और व्यापारिक शक्ति सीमित होती है, तो चीन स्वयं को अधिक स्थिर और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। इससे वैश्विक दक्षिण के देशों में चीन की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। चौथा, यूरोप और भारत की सौदेबाजी क्षमता बढ़ेगीरू यूरोपीय देशों और भारत जैसे उभरते देशों को यह संकेत मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले बड़े व्यापारिक फैसले लागू नहीं कर सकते। इससे भविष्य की व्यापार वार्ताओं में इन देशों की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हो सकती है। पांचवां लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा मजबूतरू विश्वभर के लोकतांत्रिक देशों के लिए यह संदेश गया है कि अमेरिका में अभी भी न्यायपालिका और संविधान राष्ट्रपति की शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। इससे ष्नसम वि रूष और संस्थागत लोकतंत्र की अमेरिकी छवि को कुछ मजबूती मिली है। छठा, प्रतिद्वंद्वी देशों का प्रचार तंत्र सक्रिय होगाः रूस, चीन और कुछ अन्य देश यह तर्क दे सकते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था आंतरिक संघर्षों और संस्थागत टकरावों से जूझ रही है। वे इसे अमेरिकी नेतृत्व की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहेगा क्योंकि अमेरिकी संस्थागत व्यवस्था इसी प्रकार के संतुलन पर आधारित है। सातवां, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बलरू यदि अमेरिका के भीतर निर्णय–प्रक्रिया धीमी और विवादास्पद होती है, तो अन्य शक्ति मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। जहां तक इसके राजनीतिक निष्कर्ष की बात है, इन घटनाओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। अल्पकाल में इससे ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति की गति धीमी पड़ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह अमेरिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का भी प्रमाण माना जाएगा। इसलिए विश्व राजनीति में इसका प्रभाव दोहरा होगाकृएक ओर अमेरिकी निर्णायकता पर प्रश्न उठेंगे, दूसरी ओर अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत बढ़ रही न्यायिक सुगमता

अर्जुन राम मेघवाल

न्याय सदा से ही मानव सभ्यता का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न स्तंभ रहा है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा तथा उसके स्थायी प्रतीक सामूहिक रूप से उन संस्थागत व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता की विकास यात्रा को सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया और निरंतर आगे बढ़ने में सहायता की। मानव सभ्यता के अनवरत विकास के फलस्वरूप ज्ञान–विज्ञान और तकनीक से समृद्ध आधुनिक समाज में एक–दूसरे से जुड़े व्यक्तियों और समुदायों के आपसी संबंधों में भी विभिन्न विचारों और मतों के कारण परिवर्तन आया है, तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी उन्नति ने देश की सीमाओं से आगे जाकर विचारों के निर्बाध आदान–प्रदान को और अधिक सुगम बनाया है। अनादि काल से, एक विचार की दूसरे विचार पर श्रेष्ठता स्थापित करने की होड़ न्यायशास्त्र के विकास की एक मजबूत नींव रही है। युगों से विचारों और मूल्यों के इस अंतर्संघर्ष के बीच न्यायिक संस्थानों ने सत्य, निष्पक्षता और विधि के शासन में लोगों के विश्वास को पुनरू स्थापित करने की जिम्मेदारी निभाई है। इन्होंने एक सेतु का काम किया है जो प्रत्येक संबंधित पक्ष को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो स्वयं को अलग–थलग महसूस करते हैं, न्याय और सामूहिक कल्याण की एक व्यापक प्रक्रिया से जुड़ाव, विश्वास और सहभागिता का अनुभव कराता है। इसी स्थायी संस्थागत प्रतिबद्धता के कारण एक ऐसी सशक्त व्यवस्था निर्मित होती है जो न केवल न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए अनिवार्य है। वर्तमान संदर्भ में विकसित भारतीय न्यायशास्त्र ने स्वयं को आधुनिक चुनौतियों और उपलब्ध अवसरों के अनुरूप ढाल लिया है। हमारी संवैधानिक विरासत हमें स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं का स्वप्न साकार करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में सतत मार्गदर्शन प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय की त्रिवेणी अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श संस्थाओं और व्यक्तियों दोनों के लिए एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्र भारत को संविधान के रूप में एक आदर्श मार्गदर्शक प्राप्त हुआ जिसने हमारे राष्ट्र की प्रगति की दिशा निर्धारित की। देश की आजादी के बाद यद्यपि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, फिर भी गहरी जड़ें जमा चुकी औपनिवेशिक मानसिकता भारतीय चिंतन और मूल्यों के लिए एक बौद्धिक अवरोध बनी रही। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, उसके बाद भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए दंडात्मक कानून तथा विभिन्न नीतियों ने नियमों का एक जटिल जाल बुन दिया, जिसने देश की जनता की स्वतंत्रता को सीमित किया। 19वीं सदी की मानसिकता और 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। हमें अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों पर अपार गर्व है। फिर भी, जब हम मोदी सरकार की बारह वर्षों की विकास यात्रा पर नजर डालते हैं तो शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट और सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है जिसने नागरिकों के जीवन को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है। वर्ष 2014 को हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। यह वह वर्ष था जबकि देश में युवाओं की विशाल आबादी को देश के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाले तीव्र गति से विकसित हो रहे भारत की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में संपूर्ण शासन व्यवस्था ने रिफॉर्म एक्सप्रेस से प्रेरित विकास की प्रक्रिया को तेजी से अपनाते हुए सशक्तिकरण की शक्ति का परिचय दिया है। इसकी यात्रा को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि यह जमीनी स्तर से श्ईज ऑफ लिविंगश्र को बढ़ावा देने का प्रयास है। साथ ही, राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण को शीर्ष स्तर से लागू करना भी इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार, भारत की न्यायिक सुधारों की यात्रा भी व्यापकता, नवाचार और गहन सामाजिक एवं सभ्यतागत प्रतिबद्धता की एक प्रेरक गाथा रही है। यह एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें विधायी आधुनिकीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और डिजिटल नवाचार शामिल हैं। श्ईज ऑफ जस्टिसश्र हमारे लिए मात्र एक कथन नहीं है बल्कि यह एक सुधार का मंत्र है जिसमें न्याय के लिए अदालत की शरण में जाने वालों के लिए श्ईज ऑफ इंगेजमेंटश्र, अधिवक्ताओं और न्यायाधिशों के लिए श्ईज ऑफ वर्किंगश्र तथा नागरिकों के लिए श्ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंगश्र शाामिल है। न्याय हेतु अदालतों की शरण में जाने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए दिशा योजना के तहत टेली–लॉ, न्याय बंधु और प्रो बोनो सेवाओं के विस्तार ने न्याय प्राप्ति को अत्यंत सुलभ और किफायती बना दिया है। कॉमन सर्विस सेंटर के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संचालित टेली–लॉ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के 112 लाख से अधिक लाभार्थियों को अदालतों में मुकदमे दायर करने से पहले मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने का लाभ मिला है। ई–फाइलिंग और ई–सेवा केंद्र की सेवाओं ने अदालत में मुकदमा दायर करने वाले व्यक्तियों और न्यायिक व्यवस्था के बीच नियमित संवाद एवं संपर्क को और अधिक सरल बनाया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता के समन्वय का भारत का यह अनूठा मॉडल वैश्विक स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है। अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए श्ईज ऑफ वर्किंगश्र को डिजिटल और भौतिक अवसंरचना दोनों में व्यापक विस्तार द्वारा उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है। चूंकि जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका देश के अधिकांश नागरिकों के लिए न्यायिक व्यवस्था का पहला संपर्क बिंदु है, अतरू इसे सुदृढ़ करना एक अनिवार्य और व्यावहारिक प्राथमिकता बनी हुई है। इसी दृष्टि से, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत न्यायालय भवन, अधिवक्ता कक्षों, आवासीय इकाइयों तथा डिजिटल अवसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, देश में न्यायालय भवनों की संख्या वर्ष 2014 के 15,818 से बढ़कर 22,712 हो गई है तथा अत्याधुनिक एकीकृत न्यायालय परिसरों के विकास हेतु वर्ष 2014 के बाद से अब तक 9,400.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 7200 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से शुरू की गई ई–कोर्ट चरण–द्ढद्ढद्ढ परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों को पूर्णतरू डिजिटल, पेपरलेस और एआई–सक्षम न्याय वितरण संस्थानों में परिवर्तित करना है। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, वर्चुअल कोर्ट और अदालती कार्यवाही की लाईव स्ट्रीमिंग जैसी पहलों ने न्यायपालिका को लोगों के और करीब ला दिया है तथा न्याय वितरण को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाया है। भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में नागरिकों के लिए श्ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंगश्र का होना श्ईज ऑफ जस्टिसश्र के व्यापक ढांचे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर और भाषिणी जैसे एआई– संचालित नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उपकरण उच्चतम न्यायालय के निर्णयों एवं आदेशों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, जिससे आम जनता के लिए कानूनी जानकारी अधिक सुलभ हो रही है। इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो एक सांख्यिकीय एवं विश्लेषणात्मक मंच है, 340 मिलियन से अधिक अदालती आदेशों एवं उनसे संबंधित जानकारियों के विश्लेषण तक एक क्लिक में पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, सरकार शिक्षाविदों के सहयोग से सरल और सहज विधायी प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) को बढ़ावा दे रही है ताकि कानूनों को अधिक सरल और आम नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सके। भारत में औपनिवेशिक दंड संहिता के स्थान पर नई आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने से दाण्डिक व्यवस्था के स्थान पर न्यायिक व्यवस्था स्थापित हुई है। ई–कोर्ट, ई–प्रोसीक्यूशन, ई–प्रिजन और ई–फोरेंसिक को अपराधा तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के साथ जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम है।

पीएमएस एसोसिएशन के अपर महामंत्री बने डॉ. विशाल सिंह यादव, जौनपुर का बढ़ाया मान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) उत्तर प्रदेश के द्विवार्षिक चुनाव में जौनपुर के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. विशाल सिंह यादव ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपर महामंत्री पद पर विजय हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से जनपद के चिकित्सा समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। पीएमएस एसोसिएशन का चुनाव 22 जून को संपन्न हुआ था, जबकि 26 जून को लखनऊ स्थित पीएमएस भवन में मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। डॉ. विशाल सिंह यादव को 1326 मत प्राप्त हुए, जिसके आधार पर उन्हें अपर महामंत्री निर्वाचित घोषित किया गया। परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। वर्तमान में जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ. विशाल सिंह यादव संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका, कार्यकुशलता और चिकित्सकों के हितों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करने वाले इस महत्वपूर्ण पद पर उनकी जीत को चिकित्सकों ने जनपद के लिए गौरव की उपलब्धि बताया है। उनका मानना है कि डॉ. यादव के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सकों ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनकी सफलता को जौनपुर के लिए सम्मान का विषय बताया।

उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में डॉ. यशवीर सिंह अध्यक्ष, डॉ. मोहित कुमार सिंह मुख्य उपाध्यक्ष, डॉ. क्षेत्रपाल यादव उपाध्यक्ष (सामान्य), डॉ. प्रीति सिंह उपाध्यक्ष (महिला), डॉ. शरद वैश्य महामंत्री, डॉ. प्रवीण कुमार वित्त सचिव तथा डॉ. मोहम्मद जमील अनवर संपादक पद पर निर्वाचित हुए हैं।

बिना फायर सेफ्टी वाली 55 इमारतें सील, 78 को नोटिस जारी किया गया

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए ने बिना फायर सेफ्टी के चल रहे कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, नर्सिंग होम वाली इमारतों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन अभियान चलाया। इस दौरान विरोध के बीच 55 इमारतों को सील किया गया। कुल 78 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी एलडीए के प्रवर्तन अनुभाग ने अग्निशमन विभाग व लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाया। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने टीम के साथ ठाकुरगंज, बालागंज व दुबग्गा क्षेत्र में जांच की। यहां लक्ष्य एकेडमी, अमेरिकन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, देवयोग लाइब्रेरी, रेवांता हॉस्पिटल, हनुमंत लाइब्रेरी समेत सात प्रतिष्ठान सील किए। 20 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने टीम के साथ गोमती नगर के विराज खंड, विनीत खंड, विनय खंड, विकास खंड व विराम खंड में अभियान चलाया। इसमें पत्रकारपुरम स्थित आरोही कॉम्प्लेक्स, टाइम्स इंस्टीट्यूट, एजुकेयर, टॉपर्स इंस्टीट्यूट, त्रिवेणी अलमीरा, भूमि आईएएस समेत 12 प्रतिष्ठान सील किए गए। इस जोन में 18 भवन मालिकों को नोटिस दिया गया है। आज अवकाश में भी चलेगा अभियान बिना फायर सेफ्टी वाली बिल्डिंगों के खिलाफ एलडीए का अभियान मुहर्रम के अवकाश के बावजूद शुक्रवार को भी जारी रहेगा। बुधवार से एलडीए ने अभियान शुरू किया है। दो दिन में 100 से अधिक भवन व कोचिंग संस्थान सील किए गए हैं। करीब 150 को नोटिस दिया गया है। एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे की टीम ने अलीगंज इलाके में कार्रवाई की। यहां आकार लाइब्रेरी, हनुमंत कॉम्प्लेक्स, मेकअप स्टूडियो, ध्येय आईएएस, शुभ रंजन कॉम्प्लेक्स, टॉप रैंकर, ज्ञान भवन समेत समेत 10 प्रतिष्ठान सील किए, जबकि 11 भवन मालिकों को नोटिस दिया गया है। जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने टीम के साथ हजरतगंज मेंअभियान चलाया। यहां कंचन आईएएस लाइब्रेरी, एक्मे एकेडमी समेत छह प्रतिष्ठान सील किए गए। अयोध्या रोड पर पीसीएस अधिकारी वंदना पांडेय की टीम ने साइलेंस जोन लाइब्रेरी, कोटा स्टडी फोरम समेत छह प्रतिष्ठान सील किए। जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह के नेतृत्व में टीम ने कानपुर सड़क योजना व कृष्णानगर क्षेत्र में कौटिल्य एकेडमी, दिशा कंप्यूटर, कान्हा लाइब्रेरी, सागर लाइब्रेरी, महिंद्रा कोचिंग, रेस आईएएस समेत 10 प्रतिष्ठान सील किए।

प्रवेश द्वार पर एसी के पांच आउटर यूनिट देख एसआईटी नाराज, कई और गड़बड़ियां मिलीं

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज अग्निकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बृहस्पतिवार को जलकल जोन–तीन कार्यालय का दौरा किया। इसके बाद टीम घटनास्थल पर भी पहुंची। हादसे वाली बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर एसी की पांच आउटर यूनिट और दो एग्जास्ट फैन लगे देख टीम ने विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। एसी की आउटर यूनिट और एग्जास्ट के चलते आने–जाने का एक मात्र रास्ता भी संकरा हो चुका था। अलीगंज सेक्टर–डी स्थित एक एनीमेशन कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में सोमवार को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई।

पेपर लीक, बेरोजगारी और अपराध पर सरकार पूरी तरह विफल - प्रमोद कुमार सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून–व्यवस्था के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। उक्त बाते एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका आरोप था कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और पढ़े–लिखे युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से युवाओं से माफी मांगने की मांग भी की। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावे पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्या, लूट और डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर रामराज्य के सपने को तोड़ने का आरोप लगाते हुए अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और चोरी के मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेसवार्ता को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष (संगठन प्रभारी) राकेश मिश्रा, लाल प्रकाश पाल, इरशाद खान राजू, सभासद शहनवाज, सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रवेश द्वार पर एसी के पांच आउटर यूनिट देख एसआईटी नाराज

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज अग्निकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बृहस्पतिवार को जलकल जोन–तीन कार्यालय का दौरा किया। इसके बाद टीम घटनास्थल पर भी पहुंची। हादसे वाली बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर एसी की पांच आउटर यूनिट और दो एग्जास्ट फैन लगे देख टीम ने विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। एसी की आउटर यूनिट और एग्जास्ट के चलते आने–जाने का एक मात्र रास्ता भी संकरा हो चुका था। अलीगंज सेक्टर–डी स्थित एक एनीमेशन कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में सोमवार को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद यह भी सामने आया कि अग्निशमन की गाड़ियां समय नहीं पहुंच पाई थीं। यह भी चर्चा थी कि गाड़ियों को दोबारा पानी लेने के लिए भी समस्या हुई। इन बिंदुओं की जांच के लिए ही बृहस्पतिवार को एसआईटी अलीगंज सेक्टर–बी में थाने के पास स्थित जलकल जोन–तीन कार्यालय पहुंची थी। टीम ने यह पड़ताल की कि जरूरत पड़ते तो यहां से दमकल की कितनी गाड़ियों को पानी मिल सकता है। जलकल का यह कार्यालय घटना स्थल से करीब दो किमी दूरी पर है। जलकल के अधिकारियों ने टीम को बताया कि जरूरत पड़ने पर भूमिगत जलाशय से एक साथ 100 गाड़ियों को पानी दिया जा सकता है। कार्यालय में जनरेटर की भी सुविधा है। यदि बिजली न हो तो भी पानी को पंप कर गाड़ियों में भरा जा सकता है।

बीएसएनएल की नई पहल से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने युवाओं और इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष योजना शुरू की है। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का अवसर दिया जा रहा है। बीएसएनएल का दावा है कि सीमित निवेश के साथ इस योजना से जुड़कर युवा प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं।बीएसएनएल लखनऊ व्यापार क्षेत्र द्वारा जारी जानकारी के अनुसार योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है और इच्छुक व्यक्ति अभी भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।अधिकारियों के अनुसार लखनऊ व्यापार क्षेत्र में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नौ से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 30 लोगों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है और सेवा विस्तार की दिशा में कार्य शुरू किया है।योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल प्राप्त आय का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। इसके लिए चयनित उद्यमियों को अपने स्तर पर प्रकाशीय रेशा केबल नेटवर्क की व्यवस्था स्थापित करनी होगी तथा उसके माध्यम से उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करानी होगी।बीएसएनएल ने स्पष्ट किया है कि योजना से जुड़ने वाले युवाओं को तकनीकी कार्यों के लिए पूर्ण प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान नेटवर्क स्थापना, उपभोक्ता जोड़ने, सेवा संचालन और तकनीकी रखरखाव संबंधी जानकारी दी जाएगी, जिससे उद्यमी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ जनपद में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2,500 तथा शहरी क्षेत्रों में 12,500 ब्रॉडबैंड कनेक्शन संचालित हैं। आने वाले समय में दो लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ में युवक को गोली लगने से सनसनी, पुराने विवाद में हुई वारदात की आशंका

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात गोली चलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। विजयपुर के आगे किसान चबूतरा के पास एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार घायल युवक की पहचान मोनू शुक्ला उर्फ रोहित (25) निवासी रंजीतपुर सुनहरा, थाना मोहम्मदपुर खाला, बाराबंकी के रूप में हुई है, जो वर्तमान में चिनहट क्षेत्र में रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विभूतिखंड पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।घायल मोनू शुक्ला ने पुलिस को बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से उसका सैफ, शान यादव, अक्शीर, सार्थक यादव, डेविड, लकी यादव तथा दो अन्य लोगों के साथ विवाद और मारपीट चल रही थी। उसका आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोगों ने पहले उसके हाथ में तमंचा देकर वीडियो और रील बनाई थी तथा उसे वायरल करने की धमकी भी दे रहे थे।मोनू के मुताबिक बुधवार रात वह किसान चबूतरा के पास पहुंचा था, जहां दूसरे पक्ष के लोग भी मोटरसाइकिल से आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद शुरू हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद के दौरान एक तमंचे को लेकर छीना–झपटी हुई, जिसमें चली गोली मोनू के दाहिने हाथ को छूते हुए उसकी जांघ में जा लगी।घायल युवक को तत्काल डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत खतरे से बाहर और सामान्य बताई है।

प्रदेश के किसानों और ग्रामीण गरीबों को बड़ी सौगात

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महत्वपूर्ण स्वीकृति पत्र सौंपते हुए किसानों और ग्रामीण आवास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं।लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब किसान 24 जून से 8 जुलाई तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इस निर्णय से उन किसानों को विशेष लाभ मिलेगा जो पूर्व निर्धारित अवधि में अपनी उपज नहीं बेच पाए थे।केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 6 लाख 18 हजार नए आवासों की स्वीकृति दिए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे लाखों गरीब परिवारों का पक्का घर पाने का सपना पूरा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर बनेगा।

जौहर ट्रस्ट की रामपुर में चल रही थी सरकार, अब विवि पर होगी कार्रवाई, ईडी की जांच हुई आसान

लखनऊ, (संवाददाता)। रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिजनों की जौहर ट्रस्ट अपनी अलग सरकार चला रही थी। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के आदेश में इससे जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। आयकर की जांच में सामने आया है कि जौहर ट्रस्ट सरकार की तरह फैसले ले रही थी। जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों के निर्माण में दूसरी योजनाओं में खर्च होने वाली सरकारी रकम पानी की तरह इस्तेमाल की गई। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी को जब्त करने की कार्रवाई करने की तैयारी में है। आयकर विभाग की जांच में विवि के निर्माण में बेशुमार सरकारी धन खर्च किए जाने के सुबूत मिले हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आयकर की पूछताछ में भवनों के निर्माण की कुल लागत 46 करोड़ रुपये बताई थी जबकि अधिकारियों से कराए गए सर्वे में लागत 450 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी। वहीं आयकर विभाग भी ट्रस्ट से 494 करोड़ रुपये का स्रोत पूछेगा जिसके बाद टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी वसूला जाएगा। आयकर विभाग के अधिकारी अभी इसका आकलन कर रहे हैं। ट्रस्ट ने बीते दिसंबर में आयकर विभाग के आरोपों का जवाब भी दिया था, लेकिन वह कोई तथ्यात्मक जानकारी या दस्तावेज नहीं दे सका। केवल नाम के ट्रस्टीरू जांच में सामने आया कि कई लोग सिर्फ नाम के ट्रस्टी थे। इनमें शामिल चौधरी शहरयार सलीम ने बताया कि वह डमी ट्रस्टी था। उसे जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चयन के लिए हुई बैठक में बुलाया गया था और केवल दस्तखत लेकर वापस भेज दिया गया। ट्रस्ट को आजम खान और उनके परिवार के सदस्य ही कंट्रोल और मैनेज करते हैं। यह भी सामने आया कि रामपुर के कई निजी कंस्ट्रक्शन फर्मों को अलग–अलग सरकारी ठेके दिलाए गए और बाद में उससे ट्रस्ट की संपत्तियां बनवाई गई। जौहर एसोसिएट्स और सीके एसोसिएट्स ने सरकारी अनुबंध से मिली करीब 86 करोड़ रुपये की सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल किया। इसका कोई हिसाब–किताब भी नहीं रखा गया।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक वर्ष से फरार युवक गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। कृष्णानगर थाना पुलिस ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के चर्चित मामले में करीब एक वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपना मोबाइल नंबर बदलकर दिल्ली में छिपकर नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उसे कासगंज जिले से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 19 जून 2025 को अलीगढ़ निवासी सत्यवान सिंह ने थाना कृष्णानगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री चंचल सिंह को सुभाष और उसके परिजन लगातार फोन पर अपशब्द कहकर प्रताड़ित करते थे तथा जान से मारने की धमकियां देते थे। इस मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर उनकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में थाना कृष्णानगर में मुकदमा संख्या 295/2025 धारा 108, 352 और 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया था।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित की थीं। पुलिस टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, स्थानीय सूचना तंत्र और अन्य तकनीकी माध्यमों की सहायता से आरोपी की लगातार तलाश की। इसी क्रम में 24 जून 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कासगंज जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित मजीदपुर से आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी चंचल सिंह से पहले से जान–पहचान थी और दोनों के बीच नियमित रूप से मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी। आरोपी के अनुसार 25 मई 2025 को बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान आवेश में आकर उसने चंचल सिंह से फांसी लगाने जैसी बात कह दी थी।आरोपी ने बताया कि अगले दिन 26 मई 2025 को उसे जानकारी मिली कि चंचल सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

मंडल कमीशन के मसीहा वीपी सिंह को जयंती पर किया गया याद, सामाजिक न्याय पर संगोष्ठी आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती पर राजधानी लखनऊ में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। होटल क्लार्क अवध में मंडल मसीहा मेमोरियल सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों ने वीपी सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय का अग्रदूत बताया।वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल नासीर नासिर की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व मंत्री एवं लोकसभा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का विषय ष्सामाजिक न्याय में वीपी सिंह की भूमिकाष् रहा, जिस पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए।मौलाना मोहम्मद मुस्तफा मदनी नदवी ने कहा कि पवित्र कुरआन इंसानों के साथ न्याय, भलाई, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में इसी सोच को आगे बढ़ाया।मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि वीपी सिंह ने उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया जो लंबे समय तक व्यवस्था से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उठाए गए कदमों के कारण उन्हें राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन आज देश के करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉ. बी.पी. अशोक ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों में शामिल करना चाहिए। वहीं मऊ नगरपालिका के चेयरमैन अरशद जमाल ने अपने क्षेत्र में वीपी सिंह की स्मृति में एक स्मारक स्थापित करने की घोषणा की।संगोष्ठी को प्रोफेसर महेंद्र कुमार मौर्य, डॉ. वीरेन्द्र कुमार यादव, रामचंद्र पटेल, राजेश सिंह, हृदय राम, विपत्ति सिंह यादव, पूर्व विधायक कुबैर भंडारी और रामसागर पाल समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया

जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा है कि जनता की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा और नगर विकास विभाग से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। इनमें नगर निकायों की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की समस्याएं, विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं क्षमता वृद्धि, विद्युत आपूर्ति में बाधा, आवास योजनाओं का लाभ, सड़क निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था से जुड़े प्रकरण प्रमुख रूप से शामिल रहे।मंत्री ए.के. शर्मा ने एक–एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक राहत दिखाई देनी चाहिए। जनता की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए।

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू ने उठाये ट्रस्ट, पुलिस और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट में कथित भ्रष्टाचार, दान गबन और निर्माण कार्य में घोटाले के आरोपों पर करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया।अयोध्या में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू ने ट्रस्ट, पुलिस और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान, चढ़ावे और निर्माण कार्य में कथित अनियमितताएं और चोरी हुई है। सूरज पाल अम्मू ने कहा कि एसआईटी की क्लीन चिट स्वीकार नहीं है और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाना चाहिए।उन्होंने मांग की कि नए ट्रस्ट में स्थानीय लोगों, साधु–संतों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े परिवारों को शामिल किया जाए।अम्मू ने आरोप लगाया कि आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने किसी की रिमांड नहीं ली और आगे की पूछताछ भी नहीं की।उन्होंने कहा कि इस रवैये से पूरे मामले में समझौते की आशंका पैदा होती है।करणी सेना ने चेतावनी दी कि यदि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पहले उत्तर प्रदेश और फिर पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा।प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर भी निर्माण सामग्री में कथित कमीशनखोरी और घोटाले के आरोप लगाए गए। करणी सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर बयान देने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कथित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सीवर लाइन पाइप बिछाने का कार्य अधूरा होने के चलते सड़कों पर दिखाई दे रहे गड्ढे

स्थानीय लोग व राहगीर हो रहे चोटिल,कार्यदाई संस्थान व विभाग मौन

अयोध्या।शहर के अमानीगंज कालोनी के अलावा शहर के सभी कालोनियों, मुहल्लों, मुख्य मार्गों पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है।देखा जाये तो पिछले कई माह से शहर के वजीरगंज, हैदरगंज, फतेहगंज ओवर ब्रिज से देवकाली तिराहा, शक्तिनगर कालोनी,अश्विनी पुरम कालोनी, रीडगंज तिराहा,गुरु नानक पुरा,बछड़ा सुल्तानपुर,साहबगंज, के अलावा कई प्रमुख मार्गों व मोहल्लों, कालोनियों व प्रमुख मार्गो पर यह गंभीर समस्या बनी है।इन जगहों पर मुहल्लों व गलियों मे पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे है।जहाँ पर बड़े–बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं।यहां पर रह रहे स्थानीय लोगों व राहगीरों का मानना है की आने वाले बारिश के दिनों में ये गड्ढे काफी कष्टकारी साबित होंगे।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित कार्यदाई संस्था व विभाग ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो शहर के कई मुहल्लों,कालोनियों, मार्गो पर सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य जल निगम के अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराई जा रही है।जहां–जहां पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है वहां पर या तो कार्य अधूरा है या फिर उन जगहों पर बड़े–बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं।वही गड्ढे पाटने के नाम पर कुछ मिट्टी आदि संबंधित विभाग या कार्यदाई संस्था द्वारा डाल दी जा रही है।जो हल्की सी बारिश मे और मुसीबत बन रही है।जबकि अभी पूरी बारिश बाकी ही है।इधर से गुजरने वाले राहगीरों तथा स्थानीय लोगों को इस मिट्टी के चलते परेशानियों का सामना करना पड रहा है।स्थानीय लोगों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने के बाद संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने इस मार्ग को वैसे ही छोड़ दिया जिसके चलते बड़े–बड़े गड्ढे हो गए।वही इधर बारिश होने के चलते इस गड्ढे में स्थानीय लोग व राहगीर चोटिल हो रहे है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग व कार्यदाई संस्था चुप्पी साधे है।

मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ और आईएमए अयोध्या ने आयोजित किया सीएमई कार्यक्रम

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

अयोध्या। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें उपचार में होने वाली हर मिनट की देरी मरीज के मस्तिष्क की लगभग 19 लाख ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में समय पर पहचान और तत्काल उपचार न केवल मरीज की जान बचा सकता है, बल्कि उसे स्थायी विकलांगता से भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जानकारी

मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) अयोध्या द्वारा आयोजित कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (सीएमई) कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने साझा की। मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. रतीश जुयाल ने कहा कि भारत में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. रोहित कपूर ने बताया कि भारत में लगभग 10 से 12 प्रतिशत लोगों को जीवनकाल में कभी न कभी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है और यह समस्या युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों को नवीनतम चिकित्सा ज्ञान से अवगत कराने के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को और सशक्त बनाना था।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचीं। उन्होंने वशिष्ट कुंड वार्ड क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के निकट नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर शुभारंभ किया।उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने केंद्र का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ वार्ता किया।इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनका उत्साह वर्धन किया तथा उपस्थित महिलाओं, आंगन बाड़ी कार्य कर्ताओं एवं आशा बहुओं से भी बातचीत की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि आंगन बाड़ी केंद्र केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को आत्म निर्भर बनने का संकल्प लेना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, पोषण और सुरक्षित वातावरण मिले तथा महिलाओं को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए उन्होंने बताया कि जब अयोध्या धाम में आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी ली गई तो पता चला कि यहां पर्याप्त केंद्र नहीं हैं। इसके बाद तत्काल नए आंगन बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए। इसी क्रम में वशिष्ट कुंड वार्ड सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की बेहतर सुविधा मिल सकेगी वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिकेत यादव उर्फ राजू ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके वार्ड में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद श्रीमती रंजना यादव, विभिन्न विभागों के अधिकारी, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला एसओ ने महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या।शनिवार को मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने गुप्तारघाट,गुलाबबाडी,कंपनी गार्डन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर महिला आरक्षी सूमी दास,सायरा बानों सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

23 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी धारा 163 - डीएम

अयोध्या। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक एंव राजनैतिक संगठनोंध्संस्थाओंध्व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना,प्रदर्शन, जुलूस,पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक,असामाजिक,क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है।आगामी दिनों में मोहर्रम चेहल्लुम, स्वतन्त्रता दिवस,श्रावण मास में कावड़ियों द्वारा जलाभिषेक एवं श्रावण झूला मेला आदि विभिन्न त्योहारोंध्जन्म दिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगीध्शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं।बताया कि ऐसी स्थिति में आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनोंध्कार्यक्रमों के

साथ ही उल्लिखित त्योहारोंध्जन्म दिवस, परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों के दृष्टिगत जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।बताया कि शशांक त्रिपाठी, डीएम ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 (धारा 144) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकध्शान्तिध्कानून व्यवस्थाध्जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके तहत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित है।

केंद्र सरकार में हरदोई के लोकप्रिय सांसद जयप्रकाश रावत को मंत्री बनाने की मांग

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

हरदोई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत को केंद्र सरकार में हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री की जिम्मेदारी इस बार यदि राहु केतु की बुरी नजर ना लगी तो बनना तय है मालूम हो लखनऊ मंडल से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री हटाए जा रहे हैं भाजपा को एक जुझारू और पुराने भाजपा नेता सांसद को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाना टाइम माना जा रहा है स्मरण रहे हरदोई के लोकप्रिय जयप्रकाश रावत सांसद जो बहुत पुराने सांसद हैं और भाजपा के विश्वासपात्र भी हैं जिन्हें संघ का आशीर्वाद भी है उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है यदि केंद्र सरकार ने जयप्रकाश रावत को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया तो 2027 में आसपास के जिलों में दलित समाज के अतिरिक्त लोकप्रिय सांसद होने के कारण अन्य समाज के लोग भी जयप्रकाश रावत के साथ–साथ भाजपा के साथ मजबूती से खड़े दिखाई पड़ेंगे कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार तथा भाजपा कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से जयप्रकाश रावत को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की है।

करंट की चपेट में आकर लाइनमैन की मौत

अयोध्या।शनिवार भोर कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के तुलसी उद्यान के पीछे मजगंवा मंदिर के समीप ट्रांसफार्मर पर विद्युत फॉल्ट बनाने चढ़े लाइनमैन की मौत करंट की चपेट मे आने से हो गई।मिली जानकारी के मुताबिक बाराबंकी निवासी लाइनमैन राजेंद्र कुमार मौर्या लाइन सही करने करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था।स्थानीय लोगों का मानना है कि उक्त लाइनमैन द्वारा विद्युत फॉल्ट बनाते समय उसने शट डाउन नहीं लिया था और ना ही विद्युत विभाग को कोई सूचना दिया था।जब वह विद्युत फाल्ट ठीक कर रहा था कि इस दौरान विद्युत सप्लाई उस खंबे में बहाल हो गई,जिसकी चपेट में आकर लाइनमैन की मृत्यु हो गई।बताते चले की मृतक लाइनमैन की तैनाती निर्मोचन घाट विद्युत उपकेंद्र पर थी।

जीआरपी ने युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा

प्रयागराज। नैनी थाना क्षेत्र में कक्षा 9 की छात्रा ने अपने अपहरण होने की सूचना दी। फोन करके घर बताया कि 4 किन्नरों ने मेरा अपहरण कर लिया है। वह लोग मुझे ले जा रहे है। घर वाले मौके पर पहुंचा तो कोई नहीं मिला। इसके बाद छात्रा का मोबाइल बंद हो गया। सूचना पर नैनी पुलिस भारी फोर्स के साथ छात्रा के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर के बाद जीआरपी के सिपाही ने छात्रा और उसके साथ एक युवक को नैनी स्टेशन के एक बाड़े एक में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। जीआरपी दोनों को थाने लेकर पहुंची और उनके घरवालों को सूचना दी। इसके बाद नैनी इंस्पेक्टर बृजकिशोर गौतम ने जीआरपी थाने पहुंचकर पूरे मामले में युवक और छात्रा का बयान दर्ज किया। फिलहाल नैनी पुलिस ने मामले को जीआरपी को सौंप दिया है। युवक छात्रा के दूर का रिश्तेदार है। उसके साथ भागने का प्लान था। युवक बिहार का रहने वाला है। जीआरपी युवक से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार के रहने वाली एक छात्रा अपने परिवार के साथ नैनी थाना क्षेत्र के चाका में किराए के मकान में रही है। छात्रा के पिता रेलवे में गार्ड है। छात्रा कक्षा 9 की छात्रा है। घरवालों ने बताया कि छात्रा प्रिया (परिवर्तित नाम) गुरुवार की सुबह 8.30 बजे कोचिंग लिए घर से निकली थी। छात्रा करीब 11 बजे तक घर नहीं लौटी। इसके बाद घरवाले परेशान हो गए। भाई ने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। थोड़ी देर के बाद छात्रा ने घर पर फोन के बताया कि उसे चार किन्नर पकड़ लिए है और उसका मोबाइल छीन कर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद छात्रा का फोन बंद हो गया। घरवाले भागते हुए मौके पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद भाई ने तत्काल नैनी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर नैनी इंस्पेक्टर बृजकिशोर गौतम उपनिरीक्षक यश तिवारी, उत्कर्ष सिंह, बलिराम बड़ी संख्या में फोर्स के साथ जंगल में घुसकर छात्रा की तलाश करने लगे। छात्रा का लोकेशन कई जगह मिला। जहां पर पुलिस पहुंचती रही और तलाश करती रही। लगभग दो घंटे बाद जीआरपी के एक सिपाही ने दोनों को देखा तो पकड़कर जीआरपी थाने ले आई। इसके बाद छात्रा के घरवालों को सूचना दी गई। छात्रा के मिलने की खबर घरवालों को मिली तो भाई और अन्य लोग जीआरपी पहुंच गए। उधर नैनी इंस्पेक्टर बृजकिशोर गौतम भी फोर्स के साथ पहुंचे और छात्रा के साथ पकड़े गए युवक से पूछताछ की।

शीघ्र ही बनकर तैयार हो जायेगा अग्निशमन विभाग का कार्यालय व आवास

अयोध्या। जिस तरह से फायर विभाग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है अगर सबकुछ ठीक ठाक रहा तो शीघ्र ही फायर विभाग को पुलिस लाइन परिसर में खुद का चार यूनिट के कार्यालय के साथ आवास भी मिल जाएगा।इस बात की जानकारी देते हुए सीएफओ एमपी सिंह ने कि बताया कि 4 करोड़ 74 लाख रुपया इसके निर्माण के लिए मुख्यालय द्वारा मुहैया कराया गया था।जिस पर बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ही फायर विभाग को अपना कार्यालय,आवास, गैराज मिल जाएगा।बताया कि इसका निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा कराया जा रहा है।बताया कि फायर विभाग का कार्यालय चार यूनिट का है,जिसमें सीएफओ, अग्निशमन अधिकारी के लिए एक कक्ष,एक अग्निशमन विभाग का कार्यालय,एक नियंत्रण कक्ष के साथ फायर विभाग के वाहनों को खड़ी करने के लिए गैराज का भी निर्माण भी हो रहा है।बताया कि फायर कर्मियों के रहने के लिए पर्याप्त संख्या मे अत्याधुनिक बैरक का निर्माण हो रहा है।यहां पर निर्माण होने के चलते पिछले कुछ महीनो से फायर विभाग के बड़े व छोटे वाहन के साथ फायर कर्मियों को राजकीय इंटर कलेज में शिफ्ट किया गया है बताते चलें कई दशकों से पुलिस लाइन परिसर में स्थित टीन के नीचे ठंडी, गर्मी व बरसात में फायर विभाग के कर्मी रह रहे थे।बताते चले कि पिछले वर्ष महानिदेशक फायर विभाग ने निरीक्षण के दौरान यह दशा देखकर इसे ठीक करने का निर्णय लिया और इसके निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए साथ ही साथ पत्राचार के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह को निर्देश दिए थे,जिसके चलते अब फायर विभाग को चार यूनिट का अपना कार्यालय, बैरक शीघ्र ही मिल जाने की उम्मीद है।

डॉ. कुमार सर्वोत्तम का नवाचार बना मिसाल, भारतीय पेटेंट से बढ़ा एम्स का गौरव

गोरखपुर, (संवाददाता)।वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में एम्स को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। संस्थान के प्रोफेसर डॉ. कुमार सर्वोत्तम की ओर से विकसित कम लागत वाले स्वदेशी शोध उपकरण को भारतीय पेटेंट प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि न केवल एम्स गोरखपुर बल्कि देश में स्वदेशी अनुसंधान को भी नई पहचान देने वाली मानी जा रही है। "ए लो–कॉस्ट एंड पोर्टेबल, स्माल एनिमल्स डिवाइस फॉर सिमुलेशन ऑफ डिफरिंग एन्वायरनमेंटल कंडीशंस" शीर्षक से विकसित यह उपकरण छोटे प्रयोगात्मक पशुओं के लिए विभिन्न कृत्रिम पर्यावरणीय परिस्थितियों का निर्माण और नियंत्रण करने में सक्षम है। इसकी सहायता से वैज्ञानिक एक ही मंच पर ऑक्सीजन की मात्रा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायु गुणवत्ता और प्रकाश जैसी अनेक परिस्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं। डॉ. कुमार सर्वोत्तम ने इस उपकरण का विकास अपने बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यकाल के दौरान किया था। इस शोध कार्य में उनके शोधार्थी अनिल कुमार यादव ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से तैयार यह उपकरण कम लागत में बहुआयामी अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह स्वदेशी तकनीक सीमित संसाधनों वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इससे जैव–चिकित्सकीय अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। यह संस्थान के लिए गर्व का विषय है। ऐसे नवाचार 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को मजबूत करते हैं। युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

तीन फीसदी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने खेला दांव

गोरखपुर, (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल की कई सीटों पर जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। विनोद राय भूमिहार बिरादरी से आते हैं और पूर्वांचल में करीब तीन फीसदी भूमिहार हैं, जो विधानसभा चुनाव की सियासी गणित बनाने–बिगाड़ने काफी अहम रोल निभाते हैं। पांच से सात विधानसभा सीटों पर इस बिरादरी का सीधा दखल है। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहां इस बिरादरी के लोग चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित होते हैं। विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने का मजबूत संदेश दे रही है। इसके पहले सहजानंद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया था। दोनों नेता आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मेंहदावल (संत कबीर नगर) में भूमिहार बिरादरी की संख्या ज्यादा है। ऐसे में संगठन ने इस बिरादरी की प्रभावी भूमिका को बनाए रखने का फैसला लिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के सहायक आचार्य डॉ मनीष पांडेय कहते हैं, किसी भी जाति की जहां बहुलता होती है वहां समाज में जातीय समन्वय ज्यादा होता है। समाज के बीच से किसी को संगठन की कमान सौंपी जाती है तो उसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। मुझे लगता है कि भाजपा ने भूमिहार बिरादरी को आगे करके जातीय समन्वय बैठाने की कोशिश की है। अब हार जीत का अंतर बहुत कम मतों से हो रहा है तो इस फार्मूले से जरूर पार्टी को लाभ मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नियुक्ति से पूर्वांचल में बीजेपी का जातीय और सांगठनिक समीकरण और अधिक मजबूत होगा। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ महेंद्र सिंह कहते हैं, भाजपा ने बड़ी सूझबूझ के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भूमिहार बिरादरी से आने वाले विनोद राय को दी है। पूर्वांचल में भूमिहार बिरादरी अपने अलग रुख और राजनीतिक हैसियत के कारण विशेष महत्व रखती है। शैक्षणिक, बौद्धिक और आर्थिक तौर पर मजबूत माने जाते हैं और सामाजिक रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से बिरादरी के बीच पकड़ बनाए रखने की रणनीति मानी जा रही है।

भारत सेवाश्रम संघ में पांच दिवसीय सत्संग समारोह का शुभारंभ

गोरखपुर, (संवाददाता)। एकादशी के पावन अवसर पर बृहस्पतिवार को भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा के प्रांगण में पांच दिवसीय सत्संग समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। आध्यात्मिक वातावरण, भक्तिभाव और वैदिक परंपराओं के मध्य आरंभ हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सेवाश्रम संघ, गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष स्वामी निश्रेयसानंद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।दीप प्रज्ज्वलन के साथ ही पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश गूंज उठा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।